



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 940 राँची, मंगलवार, 14 अग्रहायण, 1939 (श०)  
5 दिसम्बर, 2017 (ई०)

#### खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

-----  
अधिसूचना  
3 मार्च, 2017

संख्या- खा.आ. 06 (उप. फो.)-02/2014 - 955-- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-10 (1)(क) तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित झारखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2016 के नियम-3 एवं 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में अध्यक्ष के पद पर पूर्णकालिक रूप से नियुक्त किया जाता है:-

#### जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में अध्यक्ष पद के लिए

क्र.सं.	पदनाम	कार्यालय	स्थान	चयनित उम्मीदवार का नाम
i	अध्यक्ष	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम	गोड्डा	श्री सीताराम प्रसाद, 2/3 मुकुन्द अपार्टमेंट, वर्द्धमान कम्पाउण्ड, ज्ञान रंजन पथ, राँची, पिन- 834001

ii	अध्यक्ष	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम	हजारीबाग	श्री अरूण कुमार गुप्ता, सी-2, माँ लक्ष्मी ब्लॉक, एस.वी.आई. टावर, हरीहर सिंह रोड, बरियातू, राँची
iii	अध्यक्ष	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम	पश्चिमी सिंहभूम	श्री मोहन चैबे, फ्लैट नं.-108 (प्रथम तल्ला), श्रीराम कृष्ण इन्क्लेव, एतलहातू रोड, ग्रीन पार्क, थाना- बरियातू न्यू एरिया, मोराबादी, राँची-834008
iv	अध्यक्ष	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम	सरायकेला खरसावाँ	(सरायकेला खरसावाँ अतिरिक्त प्रभार के रूप में)
v	अध्यक्ष	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम	देवघर	श्री अवधेश मल्ल, सेक्टर-पाई, ग्रेटर नोयडा, जिला- गौतम बुद्ध नगर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-201310
vi	अध्यक्ष	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम	दुमका	श्री राम नरेश मिश्रा, ग्रीन रेसीडेन्सी, फ्लैट नं.- 402, ब्लॉक-ए., चैथा तल्ला, बरियातू, राँची, पिन- 834009
vii	अध्यक्ष	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम	जामताड़ा	(जामताड़ा अतिरिक्त प्रभार के रूप में)

2. (क) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्य पाँच वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष के उम्र तक, इनमें से जो भी पहले (न्यूनतम) हो, तक अपने पद को धारित करेंगे । अपने कार्यकाल से पूर्व भी अध्यक्ष/सदस्य अपने पद से सरकार द्वारा झारखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2016 के नियम 3 (ब)(iii) के तहत पदच्युत हो सकते हैं ।

(ख) जब सेवानिवृत्त न्यायाधीश/न्यायिक सेवा के कैंडर के कोई पदाधिकारी जिला फोरम में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होंगे तो उन्हें सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त अंतिम निर्धारित वेतन घटाव पेंशन की राशि प्राप्त होगी । साथ ही उन्हें जिला न्यायाधीश के लिए उपलब्ध सभी तरह के भत्ते, अनुमान्य लाभ, मकान किराया भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता भी उपलब्ध होंगे ।

(ग) जिला फोरम के अध्यक्ष एस.टी.डी. फोन की सुविधा के साथ अपने निवास पर टेलिफोन की सुविधा के लिए पात्र होंगे, लेकिन इसमें दूरभाष बिल प्रति माह रु. 500 (रूपये पाँच सौ) मात्र से अधिक का नहीं होना चाहिए ।

(घ) जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्य सरकारी दौरे पर राज्य सरकार के ग्रेड पे-7600 के अधिकारी के लिए स्वीकार्य, यात्रा एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे ।

3. चयनित अध्यक्ष को झारखण्ड उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 2016 के नियम 3(ब)(i)/6(ब)(i) के अनुसार उन्हें योगदान करने से पूर्व यह घोषणा-पत्र (केन्द्रीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-1) जमा करना होगा कि वे और उनके रिश्तेदार किसी भी ऐसे वित्तीय या अन्य लाभ को प्राप्त नहीं करेंगे, जिससे कि उनके अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्यों के प्रभावित होने की संभावना हो । भविष्य में यदि किसी के मामले में यह पता चला कि उन्होंने अपने आवेदन में वस्तुस्थिति एवं सत्य को छिपाया है तो उनकी नियुक्ति बिना कारण पूछे समाप्त कर दी जाएगी ।

4. अध्यक्ष की नियुक्ति जिन जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरमों के लिए की जा रही है, उस जिले के उपायुक्त को अपना योगदान देंगे । नवनियुक्त अध्यक्ष के योगदान के साथ प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों की जाँच संबंधित पदाधिकारी कर संतुष्ट हो लेंगे । इसके उपरान्त संबंधित पदाधिकारी नवनियुक्त अध्यक्ष के योगदान की स्वीकृति की संस्तुति राज्य आयोग को भेजेंगे । तत्पश्चात् अध्यक्ष, झारखण्ड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राँची द्वारा योगदान की स्वीकृति प्रदान की जायगी ।

5. अध्यक्ष इस रूप में पद पर न रह जाने पर किसी ऐसे संगठन में कोई नियुक्ति ग्रहण नहीं करेगा या उसके प्रबन्धन या प्रशासन से संबद्ध नहीं रहेगा जो जिस तारीख को वह इस पद पर न रह गया हो उस तारीख से पाँच वर्षों की कालावधि के दौरान अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही की विषय-वस्तु रहा हो ।

6. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर नवनियुक्त अध्यक्ष द्वारा अपने पद पर अनिवार्य रूप से योगदान समर्पित किया जाएगा । निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने पद पर योगदान नहीं करने पर उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी एवं उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा ।

7. तात्कालिक व्यवस्था के तहत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, पश्चिमी सिंहभूम के नवनियुक्त अध्यक्ष ही जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, सरायकेला-खरसावाँ के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार में अगले आदेश तक रहेंगे ।
8. तात्कालिक व्यवस्था के तहत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, दुमका के नवनियुक्त अध्यक्ष ही जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, जामताड़ा के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार में अगले आदेश तक रहेंगे ।
9. अतिरिक्त प्रभार हेतु संबंधित अध्यक्ष को नियमानुसार टी.ए./डी.ए. देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**विनय कुमार चौबे,**  
सरकार के सचिव ।

-----